

## उत्तराखण्ड में कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना(डॉस्प) का क्रियान्वयन: जैविक खेती हेतु एक अभिनव प्रयोग

### (An Innovative Practice for Organic Farming)

डॉ० राकेश चन्द्र छिम्वाल,  
कोटद्वार रोड, लखनपुर,  
रामनगर—नैनीताल।

**सारांश :** सत्रह वर्ष पूर्व गठित हुआ उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि अपने अस्तित्व बचाने को संघर्ष कर रही है। कृषि के घाटे का सौदा होने के कारण पलायनवादी प्रवृत्तियां तेज हुई हैं। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना (डॉस्प) प्रारम्भ की गयी। परियोजना ने कई अभिनव पहलें की। डॉस्प ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये। किन्तु गलत प्राथमिकताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं की मनमानी के कारण परियोजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

**शब्द कुंजी** – कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना (Diversified Agriculture Support Project- DASP), विकासखण्ड तकनीकी टीम, स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह।

#### 1. प्रस्तावना

शेष भारत की तरह उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का आधार भी कृषि है। यहाँ की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है (भारत 2017, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली)। नवसृजित राज्य उत्तराखण्ड का लगभग 88 प्रतिशत भाग पर्वतीय है, जिसकी अधिकांश कृषि वर्षा आधारित है। वर्षा आधारित कृषि होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के कृषि उत्पाद जैविक हैं। वहीं उत्तराखण्ड के 12 प्रतिशत मैदानी भाग की लगभग 95 प्रतिशत कृषि सिंचाई आधारित है, जो अपनी उत्पादकता में गंगा के मैदानों के समकक्ष है।

निम्न उत्पादकता, विपणन व्यवस्था का आभाव, पिछड़ी कृषि तकनीकें, प्रकृतिक विपदाएँ आदि समस्याओं के कारण पर्वतीय कृषि घाटे का सौदा है। किन्तु पर्वतीय कृषि जैव कृषि होने के साथ-साथ विविधिकृत कृषि है, जिसमें कृषि के साथ ही फल-सब्जियों की खेती, पशुपालन आदि कार्य पूर्व से ही किये जाते रहे हैं। मैदानी भागों में हरित क्रांति के आगमन के पश्चात से लाभदायक कृषि की जा रही है किन्तु मैदानी भागों में कृषि विविधता का ह्रास हुआ है तथा कृषि लागत बढ़ती जा रही है। साथ ही अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण भूमि विषाक्तता बढ़ी है तथा उत्पादन की वृद्धि दर भी स्थिर हो गयी है। उक्त सभी समस्याओं के दृष्टिगत रखते हुए अविभाजित उत्तर प्रदेश में कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना (डॉस्प) की रूपरेखा तैयार की गयी।

#### 2. परियोजना का उद्देश्य

कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना (डॉस्प) का उद्देश्य कृषि में विविधिकरण को बढ़ावा देकर उत्तराखण्ड की कृषि को लाभदायक बनाना था। साथ ही जैविक खेती का प्रोत्साहित करना था। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परियोजना को छः घटकों यथा कृषि घटक, उद्यान घटक, पशुपालन व दुग्ध घटक, रेशम घटक, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग एवं ग्रामीण हाट घटक, तथा सहभागिता प्रबन्धन घटक में विभाजित किया। परियोजना के घटक वार उद्देश्य निम्न प्रकार थे।

##### 2.1 कृषि घटक

- एकीकृत पादप पोषण प्रबन्धन (I.P.N.M.) का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण
- एकीकृत नापीजीव प्रबन्धन (I.P.M.) का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण
- कृषक बीज ग्रामों की स्थापना।
- जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु जैविक ग्रामों की स्थापना।
- किसान दिवसों का आयोजन

- कृषकों व विभागीय कर्मियों का कौशल वृद्धि हेतु शैक्षिक भ्रमण एवं अन्य क्रिया-कलाप

## 2.2 उद्यान घटक

- फल सब्जी एवं पुष्प एवं इत्र वाले पुष्प क्षेत्रों का विकास करना।
- उन्नत प्रजाति के बीजों एवं सामग्रियों को उपलब्ध करवाना।
- कृषकों एवं विभागीय तकनीकी कर्मियों के कौशल में वृद्धि करना
- पॉलीहाउस तकनीकी से नर्सरी उत्पादन को बढ़ाना

## 2.3 पशुपालन एवं दुग्ध घटक

- पशु प्रदर्शनी का आयोजन
- पशु नस्ल सुधार कर दुग्ध विकास को बढ़ावा
- दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन करवाना
- पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण
- कृत्रिम गर्भाधान एवं पशुचिकित्सा सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु पशुपालन सेवा केन्द्र का सुदृढीकरण
- पशुपालन कल्याण षिविरो का आयोजन
- पशुप्रबन्ध, चारा विकास एवं तकनीकी को बढ़ावा देना।

## 2.4 रेशम घटक

- षहतूत पौध रोपण
- ग्रामीण बाजार का आयोजन
- उत्पाद की प्रदर्शनी लगाना
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की स्थापना
- उत्पाद की विपणन व्यवस्था
- कोया उत्पादन
- प्राथमिक रेशम उत्पादक समूहों को गठन
- स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से तकनीकी प्रसार
- कोया विक्रय हेतु बाजार की व्यवस्था

## 2.5 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग एवं हाट ग्रामीण घटक

- ग्रामीण बाजार का आयोजन।
- उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण
- उत्पाद की विपणन व्यवस्था।

## 2.6 सहभागिता प्रबन्धन घटक

- ग्रामीण सहभागी अध्ययन, सर्वेक्षण एवं बैठकों के माध्यम से कार्यक्रमों का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना कार्यक्रमों का चिन्हीकरण
- स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें कृषि आधारित गतिविधियों से जोड़ना।
- नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
- समूहों का ऋण सुविधाओं हेतु बैंकों से जोड़ने हेतु सहयोग करना
- जन जागरूकता कार्यक्रम

## 3. परियोजना की रूपरेखा

विष्व बैंक सहायतित इस परियोजना की लागत अविभाजित उत्तर प्रदेश में 160.50 मिलियन डालर आँकी गयी जिसमें 20 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का था। दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को पृथक उत्तराखण्ड राज्य गठित हो जाने पर राज्य में परियोजना की लागत 15 मिलियन डालर अर्थात् 74 करोड़ के समतुल्य आँकी गयी। औपचारिक रूप से यह परियोजना 05

वर्ष के लिए बनी और इस योजना को 30 सितम्बर 1998 से विधिवत शुरू कर दिया। नवगठित राज्य उत्तराखण्ड बनने के बाद कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना, उत्तराखण्ड के नाम से मई 2001 में स्वतंत्र इकाई के रूप में इसका अभ्युदय हुआ। इस परियोजना का राज्य स्तरीय कार्यालय 'परियोजना समन्वयन इकाई' के नाम से देहरादून में खोला गया। यह परियोजना नव सृजित राज्य उत्तराखण्ड के देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं उत्तरकाशी जनपदों में संचालित की गयी। इन पाँच जिलों के 27 विकासखण्डों का चयन इस परियोजना हेतु किया गया।

### 3.1 परियोजना का कार्यक्षेत्र

**तालिका 01 परियोजनान्तर्गत जनपदों में विकासखण्डवार विवरण  
(चयनित ग्रामों व परिवारों की संख्या)**

क्र०सं०	जनपद	विकासखंड	ग्रामों की संख्या	परिवारों की संख्या
1.	देहरादून	सहसपुर	86	3294
2.		विकासनगर	63	2560
3.		डोईवाला	77	9148
4.		रायपुर	109	4242
5.		कालसी	76	1815
6.		चकराता	67	1606
<b>योग</b>			<b>478</b>	<b>22665</b>
7	नैनीताल	हल्द्वानी	69	2003
8		रामनगर	65	1500
9		कोटाबाग	40	1120
10		भीमताल	58	1300
11		रामगढ	101	1280
12		बेतालघाट	69	600
<b>योग</b>			<b>406</b>	<b>7803</b>
13	उधमसिंह नगर	जसपुर	27	5649
14		काशीपुर	19	6209
15		गदरपुर	17	9660
<b>योग</b>			<b>63</b>	<b>21518</b>
16	अल्मोड़ा	ताडीखेत	16	611
17		भिक्यासैण	16	1081
18		सल्ट	16	621
19		लमगड़ा	16	943
20		धौलादेवी	17	984
21		हवलबाग	16	931
<b>योग</b>			<b>97</b>	<b>5171</b>
22	उत्तरकाशी	चिन्चालीसौड़	16	1020
23		नौगांव	48	2510
24		डुंडा	16	2042
25		पुरोला	16	1235
26		भटवाड़ी	16	1606
27		मोरी	16	603
<b>योग</b>			<b>128</b>	<b>9016</b>

स्रोत: –Status Report-ICR

Prepared for ICR Mission 27-31 March 2004  
Diversified Agricultural Support Project, Uttranchal

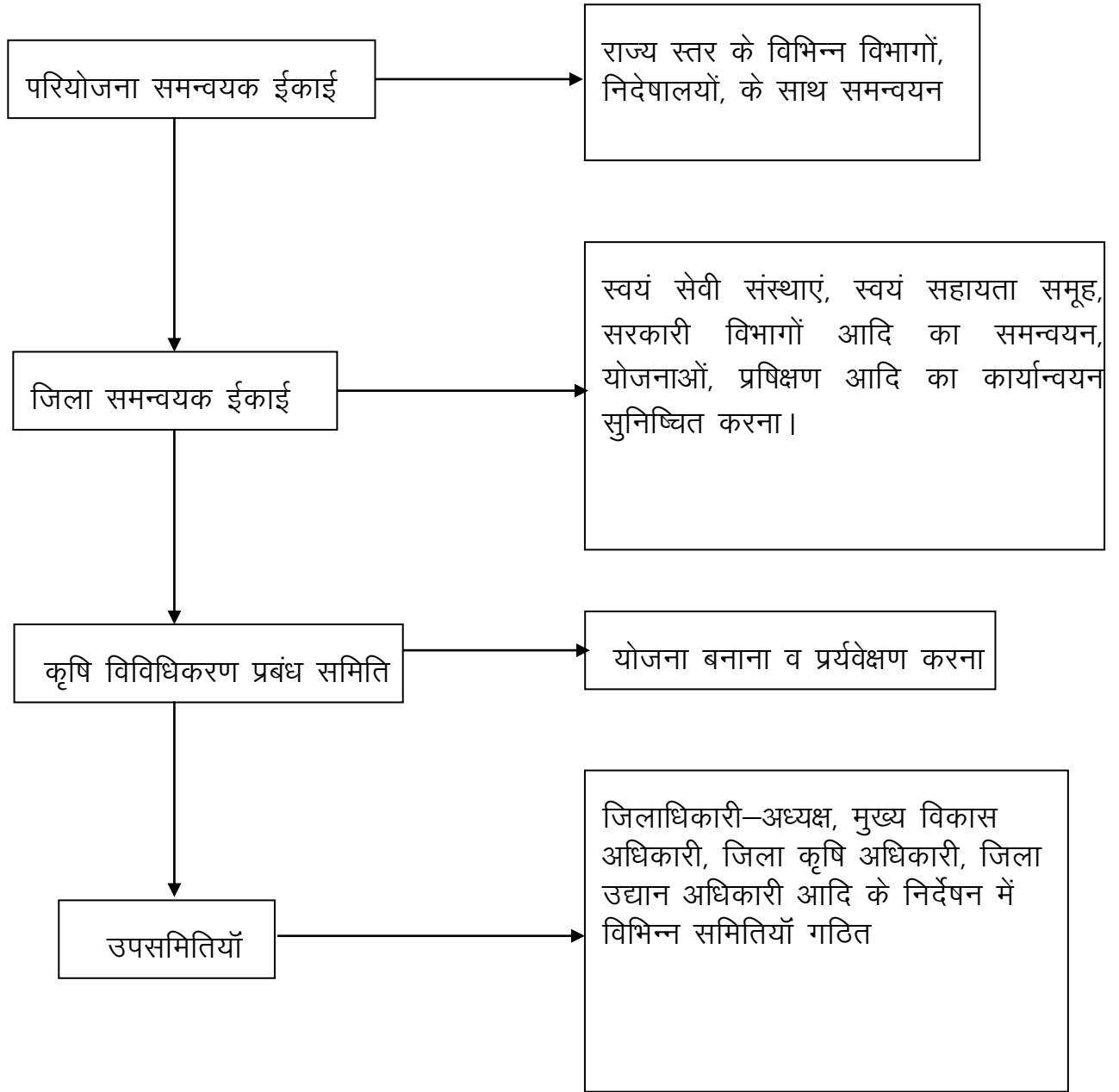
### 3.2 परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति

उत्तराखण्ड में परियोजना के संचालन हेतु 18 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया। साथ ही विभिन्न तकनीकी प्रसार हेतु विभिन्न सरकारी विभागों यथा कृषि निदेशालय, देहरादून (कृषि घटक के कार्यान्वयन हेतु), उद्यान निदेशालय, रानीखेत (उद्यान घटक के कार्यान्वयन हेतु), रेशम निदेशालय, देहरादून (रेशम घटक के कार्यान्वयन हेतु), को भी परियोजना से जोड़ा गया। इन विभागों से एक-एक अधिकारी को परियोजना का नोडल अधिकारी बनाया गया। परियोजना का एक अन्य मुख्य कार्य कृषकों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाना था, जिस हेतु जी0बी0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तराखण्ड) को प्रौद्योगिक विकास एवं प्रसार के लिए परियोजना से जोड़ा गया। परियोजना के मूल्यांकन हेतु भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को उत्तरदायित्व दिया गया। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल को अपनाने का प्रयास किया गया। इस हेतु जैविक कृषि के क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाएँ जैसे सूपा बायोटेक, नैनीताल, मेपल आर्गेनिक्स देहरादून, उत्तराखण्ड बीज प्रमाणीकरण संस्था, देहरादून आदि की सहायता ली गयी।

राज्य स्तर पर समन्वयन हेतु स्थापित कार्यालय 'परियोजना समन्वयक ईकाई, देहरादून' के निर्देशन में जिला स्तर पर विभिन्न विभागों व स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ 'जिला समन्वयन ईकाई' समन्वयन स्थापित करती थी। यह ईकाई परियोजना में चयनित विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में चल रहे कार्यों का, स्वयं सहायता समूहों का संचालन व मार्गदर्शन करती थी। साथ ही साथ मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण, भ्रमण आदि कार्यों का क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर दो उप-समितियों का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जाती थी।

कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना के उच्च निष्पादन हेतु कृषि विविधिकरण प्रबन्ध समिति (ADMS) का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत किया गया। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा कृषक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य थे। जिला परियोजना समन्वयक इस समिति के सचिव व कोषाध्यक्ष थे। समिति जिला स्तर पर विभिन्न रेखा विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वित रूप से कार्य करती। जिससे परियोजना में चयनित ग्रामों में लक्षित गतिविधियों का सुगम संचालन हो सके। परियोजना के अधिकारियों के अनुसार कृषि विविधिकरण प्रबन्ध समिति की बैठकों में कृषकों को गम्भीरतापूर्वक सुना जाता तथा कार्यक्रमों को अधिक किसान उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किये जाते।

परियोजना का प्रशासनिक रूप एवं कार्य निम्न रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। रेखा विभागों व संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के समन्वित प्रयास से तकनीकी सेवाओं व कौशल को काश्तकारों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए विकास खण्ड स्तर पर विकासखण्ड तकनीकी टीम (Block Technical Team – B.T.T.) का गठन किया गया।



स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर सम्पादित

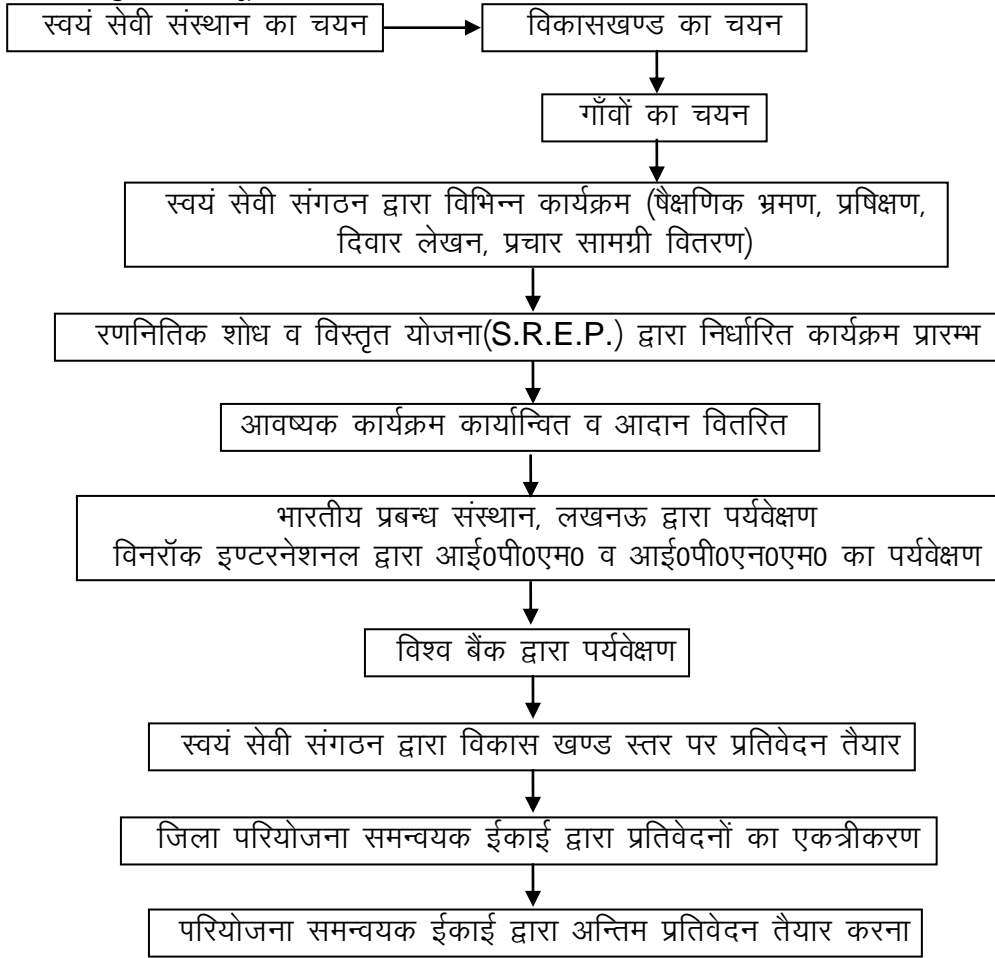
चित्र संख्या- 01

### कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना का प्रशासनिक स्वरूप एवं कार्य

#### 3.3 परियोजना का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

हर माह परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाता था। जनपदों में परियोजना गतिविधियों के नियमित अनुश्रवण के लिए भारतीय प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ के अधिकारी हर माह परियोजना अन्तर्गत ग्रामों का भ्रमण करते थे। साथ ही विश्व बैंक भ्रमण दल द्वारा नियमित अंतराल पर परियोजना कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता था।

प्रति वर्ष नयी जिला कार्ययोजना बनायी जाती थी, जिससे पिछले वर्ष की कार्ययोजना के अनुभवों का व्यापक उपयोग किया जाता था। पाँच चरणों में बनी जिला कार्ययोजना को स्वयं सेवी संस्थाओं व विभागों द्वारा लागू किया जाता था, साथ ही अनुश्रवण व मूल्यांकन प्रारम्भ हो जाता था। इसे निम्न फ्लो चार्ट द्वारा समझा जा सकता है।



स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर सम्पादित

### चित्र संख्या-02

### परियोजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन की सोपानीकृत प्रक्रिया

#### 4. निष्कर्ष एवं सुझाव

##### 4.1

परियोजना के अन्तर्गत विकास के लिए मुख्य रणनीति प्रदर्शन रही। सभी गतिविधियों के अन्तर्गत प्रदर्शन व प्रशिक्षण प्रमुख रहा। प्रत्येक विकासखण्ड में कुछ कृषकों का चयन कर उनके खेतों में अभिनव प्रयोग किये जाते तथा अन्य किसानों को उनके अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता अर्थात् प्रदर्शन व प्रशिक्षण से जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। किन्तु उन्ही कृषकों का चयन किया गया जो सम्पन्न थे तथा चयनित स्वयं सेवी संगठनों (N.G.O.) के सम्पर्क में थे।

#### 4.2

डॉस्प द्वारा लिए गये विभिन्न घटकों के आधार पर अनुभव यह रहा है कि विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं आदि से गरीबों की अपेक्षा ग्रामीण समाज के साधन सम्पन्न लोगों को अधिकतम लाभ मिला है। बड़े किसानों के पक्ष में साधन पक्षपात ही वर्तमान असमानता फैलाने वाला प्रमुख कारक है।

#### 4.3

परियोजना का कार्यान्वयन स्वयं सेवी संगठन (N.G.O.) के माध्यम से किया गया। किन्तु इनके चयन में परियोजना द्वारा स्थापित मानकों का पालन नहीं किया गया। चयनित कुल 18 स्वयं सेवी संगठन (N.G.O.) में से कुछ ही उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में कृषि संबंधी कार्य करने वाली संस्थाएं थीं।

#### 4.4

जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाली परियोजना में कृषि घटक के अन्तर्गत I.P.N.M. (Intrigeted Plant Nutrition Menegment) के तहत भूमि हेतु रासायनिक उर्वरकों की संस्तुति की गयी।

#### 4.5

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृषकों से अधिक प्रशिक्षण स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का रहा। शोध अध्ययन के द्वारा यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि कुछ भ्रमण कार्यक्रम केवल मनोरंजन के लिए थे।

#### 4.6

परियोजना के अन्तर्गत कृषक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जो वर्तमान में भी प्रासांगिक हैं। परियोजना ने जैविक कृषि के महत्व को स्थापित किया तथा कृषकों में जैविक कृषि के प्रति रुचि उत्पन्न हुई।

#### 4.7

परियोजना ने राज्य में वर्तमान में कई माध्यमों से बढ़ावा दी जा रही पॉली हाउस/पॉली टनल आदि तकनीकों को सर्म्थन प्रदान किया।

#### 4.8

परियोजना के द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत की गयी फसलों/फलों यथा कीवी आदि को उत्तराखण्ड में कृषकों द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके परिणाम वर्तमान में दिखायी दे रहे हैं।

#### 4.9

परियोजना के अन्तर्गत कुछ सम्पर्क मार्गों व पुलों का निर्माण किया गया। यद्यपि ये निर्माण कार्य केवल देहरादून जनपद में ही हुआ तथापि इस निर्माण कार्य से जनपद देहरादून में स्थायी आस्तियों का निर्माण हुआ।

#### 4.10

परियोजना ने अन्तर परियोजना ग्रामों में मध्य असन्तोष उत्पन्न किया। परियोजना के अन्तर्गत चयनित कृषकों एवं परियोजना से छूटे कृषकों के मध्य असन्तोष उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार लगभग 75 करोड़ रुपये की कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना (डॉस्प) से वांछित परिणामों की प्राप्ति के प्रयास नहीं हुए। यह परियोजना अपने सामने महत्वपूर्ण उद्देश्य को रखने के बावजूद उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत नहीं रही तथा भ्रष्टाचार एवं कुप्रबन्धन का शिकार रही। उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिले जो जैविक उत्पाद उत्पादित करते हैं, के कृषि विकास की एकमात्र आवश्यकता विपणन सुविधाएँ हैं। परियोजना इस आवश्यकता को समझने में असफल रही।

संदर्भ

1. Status Report- ICR DASP Uttaranchal, Technology Development. p 27-31 March 2004.
2. छोटी सी आषा, कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना, उत्तराखण्ड।
3. Socio-Economic Impact Assessment of Diversified Agricultural Support Project, Uttaranchal, A Report by : Agricultural management Centre. Indian Institute of Management, Lucknow, Project coordination unit Dehradun, November, 2002.
4. संख्यिकीय डायरी, उत्तराखण्ड, 2015-16, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. संगठन से सशक्तता की ओर, कृषि विविधिकरण परियोजना उत्तराखण्ड, सोसायटी ऑफ पीपल फॉर डेवलपमेंट (एस0पी0डी0), देहरादून।
6. किसान की कहानी किसान की जुबानी, उत्तराखण्ड जैविक कृषि की ओर, प्रायोजक : सी0भास्कर, कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना (डॉस्प), देहरादून।
7. योजना, विकास को समर्पित मासिक, प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. भारत 2017, प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. Journal of rural development a quarterly journal of nird Vol 25 october – December 2006 No. 4, Hyderabad.